साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 27 सितम्बर 2021, वर्ष-7, अंक-26

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

योगी के साढ़े चार साल बेमिसालः सीएम ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, बोले

एमएसपी पर हो रही खरीद, गन्ना किसानों को 1.43 लाख करोड़ का भुगतान

- » यूपी में 1.38 लाख निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए
- » स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण
- » उज्ज्वला योजना में 1.56 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए
- » पीएम स्वनिधि से 08 लाख 80 हजार स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित
- » किसान सम्मान से 2.53 करोड़ 98 हजार किसान लाभान्वित

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साढ़े चार साल बेमिसाल रहे। दरअसल, हाल ही में यूपी सरकार के साढ़े चार पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए बताया कि किस तरह उनकी सरकार किसान, महिलाओं, गरीबों, छात्रों और युवाओं के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। प्रदेश सरकार केंद्र की 44 योजनाओं के क्रियान्वयन में देशव मं अव्वल रही है। अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों, नौजवानों, गरीबों, महिलाओं समेत अन्य लाभार्थियों को 05 लाख करोड़ की धनराशि डीबीटी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में राज्य सरकार को अब तक के कार्यकाल में पूरी सफलता मिली है।

पंचायत में महिलाओं का दबदबा

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित किया गया है। वर्तमान में मिशन शक्ति का तृतीय चरण गतिमान है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इत्यादि योजनाएं लागू की गई हैं। पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाएं चुनी गई हैं। इससे उनके सशक्तीकरण को गति मिल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में 30,000 महिला आरक्षियों की भर्ती की गई है।

एमएसपी पर पीओएस| प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग करते हुए किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की सहूलियतें विकसित की हैं। एमएसपी के तहत किसानों से उनकी उपज की खरीद में ई-पॉप सिस्टम के उपयोग से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है।

गन्ना किसानों के अच्छे दिन| मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में चीनी मिलों को बंद कराया गया, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने बंद चीनी मिलों को चालू कराया। यहां तक कि कोरोना काल में सभी 119 चीनी मिलें कार्यरत रहीं। सरकार द्वारा गन्ना किसानों को अब तक 1.43 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सहायतार्थ योजनाओं में वर्ष 2012-17 के मुकाबले वर्ष 2017-21 तक लगभग दोगुनी सहायता प्राप्त हुई।

मध्यप्रदेश में मौजूदा दर पर ही मिलेगी डीएपी

अब खाद भी महंगी

प्रदेश में कहीं अतिवृष्टि तो कहीं सूखे की मार से खरीफ सीजन की फसलें खराब हो गई हैं। दूसरी तरफ रबी सीजन के लिए सरकार ने खाद के दाम बढ़ा दिए हैं। डीएपी की कमी का हवाला देते हुए डीएपी के वैकल्पिक खाद एनपीके के दामों में 500 रुपए तक की बढ़ोत्तरी की गई है। जिसका सीधा किसानों की जेब पर पड़ेगा। आर्थिक तंगी के बीच रबी सीजन की लागत ओर बढ़ जाएगी। मध्यप्रदेश में एनपीके खाद की बढ़ी हुई दरें एक अक्टूबर से लागू होगी।

विशेष संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) खाद की कीमत में वृद्धि कर दी है। अलग-अलग श्रेणी की खाद में 515 रुपए से लेकर 320 रुपए की वृद्धि प्रति पचास किलोग्राम की बोरी में की गई है। डीएपी की कीमत प्रति बोरी एक हजार 211 रुपए यथावत रहेगी। नई दरें एक अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी। राज्य की उर्वरक समन्वय समिति ने फास्फेटिक उर्वरकों की दर तय की है। समिति की बैठक में तय किया गया कि डीएपी के वैकल्पिक उर्वरक के तौर पर एनपीके की उपलब्धता को बढ़ाया जाए। राज्य सहकारी विपणन संघ के महाप्रबंधक एमके पाठक ने जिला विपणन अधिकारियों को रबी सीजन 2021-22 (एक अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022) के लिए प्रति पचास किलोग्राम के बैग की नई कीमत के आधार पर विक्रय एक अक्टूबर के बाद प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। एनपीके प्रति बोरी अब एक हजार 700 रुपए से लेकर एक हजार 550 रुपए में मिलेगी।

हमने किसानों को उत्पादन की लागत घटाने के लिए 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देना प्रारंभ किया। डीएपी की कीमत बढ़ी, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1,200 रुपए में ही डीएपी की बोरी देने का निर्णय लिया। इसमें अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 42 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है।

शिवराज सिंह चौहान, सीएम

किसानों की आय दोगुनी करने और समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात करने वाली सरकार खाद की कीमत में वृद्धि करके उत्पादन लागत बढ़ाने का काम कर रही है। कोरोना संकट और महंगाई के कारण किसान पहले से परेशान हैं और राहत की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह मूल्यवृद्धि किसान विरोधी है। उन्होंने इसे सरकार तत्काल वापस ले।

कमलनाथ, पूर्व सीएम

राज्य सहकारी विपणन संघ ने जारी किए आदेश -प्रदेश में एक अक्टूबर से नई दरें होंगी प्रभावी

डीएपी में राहत

अमोनियम फास्फेट सल्फेट की बोरी एक हजार पचास रुपए के स्थान पर एक हजार 225 रुपए में विक्रय की जाएगी। हालांकि, बोवनी के समय सर्वाधिक उपयोग में आने वाली डीएपी की कीमत में वृद्धि नहीं की गई। मार्कफेड के अपने अफसरों को निर्देश दिए कि प्रदेश में डीएपी की कमी है। इसके दाम 1211 रुपए प्रति बैग ही रहेंगे। इसलिए एनपीके का अधिक से अधिक स्टॉक किया जाए। और 1 अक्टूबर से इसे प्राथमिकता से बेचा जाए। हालांकि रबी 2021-22 के लिए निर्धारित एनपीके की विक्रय दरें रबी 2020-21 की तुलना में बहुत अधिक है।

सहकारिता सम्मेलनः मंत्रालय का पहला मंत्री बनने पर अमित शाह बोले

सहकार से समृद्धि हमारा नया मंत्र

संवाददाता, नई दिल्ली/भोपाल

देश के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं सहकारिता मंत्रालय का पहला मंत्री हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे इसके लिए मौका दिया। उन्होंने कहा कि मैं सहकारिता मंत्री के नाते देशभर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अब लापरवाही का समय समाप्त हो गया है। प्राथमिकता का समय शुरू हुआ है। इसलिए सब साथ मिलकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। सहकार से समृद्धि हमारा नया मंत्र है। शाह ने कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। यहां के विचारों, जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है। ये कोई उधार लिया हुआ विचार नहीं है। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी की अवधारणा भी खड़ी करेगा। शाह ने आगे कहा कि मैं 25 साल तक सहकारिता आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। देश पर जब-जब कोई विपदा आई है, सहकारिता आंदोलनों ने देश को बाहर निकाला है। कॉपरेटिव बैंक बिना मुनाफे की चिंता किए लोगों के लिए काम करते हैं। क्योंकि, भारत के संस्कारों में सहकारिता है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अमूल व लिज्जत सहकारिता के दो आयाम हैं। अमूल से जहां देश के करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं तो लिज्जत पापड़ से महिलाओं को रोजगार मिला है।

उच्च शिक्षा विभाग ने किया अनिवार्य-पर्यावरण को दूषित होने से बचाने शिवराज सरकार ने उठाया अहम कदम

मप्र में कॉलेज छात्रों को पौधा लगाने पर ही मिलेगी डिग्री

» आधे छात्रों ने भी लगाए तो 5 लाख हो जाएगा पौधरोपण

» प्रदेश के विवि, कॉलेज कम से कम एक गांव गोद लें

» हर छात्र एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल भी करेगा

विशेष संवाददाता, भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण और छात्रों में उसके महत्व समझाने के इरादे से नई पहल करने जा रहा है। इसके लिए विवि और महाविद्यालय अपने कार्य क्षेत्र के कम से कम एक गांव को गोद लेंगे। यही नहीं, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को अब कम से कम एक पौधा लगाना होगा, तभी उन्हें डिग्री दी जाएगी। छात्रों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग यह अनूठी पहल शुरू करने जा रहा है। छात्र को पौधा लगाने के बाद उसकी सेल्फी लेकर संबंधित लिंक पर भेजना होगी। पौधे की देखरेख भी करनी होगी। यह पहल इसलिए की जा रही है, ताकि छात्रों का पर्यावरण से जुड़ाव रहे और वे पेड़-पौधों के महत्व को समझें। इससे वे पौधों की देखरेख भी करने लगेंगे। पेड़ों को कटने से बचाएंगे और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे। अब तक छात्रों को ऐसा कोई टास्क नहीं दिया जाता जो सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ हो, लेकिन पर्यावरणीय दृष्टि से इस तरह का कदम पहली बार उठाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टी एंट्री और एग्जिट का प्रावधान किया गया है। छात्रों को पढ़ने के दौरान अधिक से अधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

एक गांव लेना होगा गोद | प्रदेश के सरकारी कॉलेजों को उनके क्षेत्र के आसपास का एक गांव गोद लेना होगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि छात्र यहां समय-समय पर जाकर स्वच्छता, स्वास्थ्य और अन्य समाजिकहित की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। जिस कॉलेज में छात्रों की संख्या एक हजार है, उसे एक यूनिट माना जाएगा और उसे कम से कम एक गांव गोद लेना होगा। यदि छात्र संख्या 5 हजार है तो ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि कॉलेज 4-5 गांवों को गोद ले।

11 लाख से ज्यादा छात्र

यूजी-पीजी को मिलाकर प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं हैं। ऐसे में यदि आधे छात्रों ने भी पौधे रोपे तो 5 लाख से ज्यादा पौधरोपण हो सकेगा। इसके लिए विभाग मॉड्यूल तैयार कर रहा है। इसके तहत कॉलेजों को इससे जोड़ा जाएगा। कॉलेज जिस कॉलेज को गोद लेंगे वहां विभिन्न मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने के साथ ही आदर्श ग्राम बनाने के लिए भी काम करेंगे, ताकि आसपास के ग्रामीण भी उनके गांव की बेहतरी के लिए प्रेरित हों।

कम से कम एक पौधा लगाने के बाद ही छात्र को डिग्री मिलेगी। इसके लिए मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। कॉलेज प्राचार्यों को भी जानकारी दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। छात्रों के प्रोजक्ट वर्क आदि में भी इसे शामिल करेंगे। वे वहां जाएंगे और गांव की बेहतरी के लिए काम करेंगे।

-मोहन यादव, मंत्री, उच्च शिक्षा

-मालवांचल में छह हजार एकड़ में बासमती और अन्य किस्मों की खेती की जा रही

उज्जैन में लहलहा रही बासमती, मालवा में मुरझाई और इंदौर बारिश ने दिया दगा

हजारों बीघा की फसल बर्बाद हो गई, किसानों ने समय से पहले फसल काटनी पड़ी

उज्जैन

अपनी खुशबू और स्वाद की वजह से बासमती चावल दुनियाभर में मशहूर है। यही वजह है मालवा के किसानों को इसकी खेती आकर्षित कर रही है। लिहाजा, इस साल मालवा अंचल (इंदौर, उज्जैन के आसपास के जिले) में लगभग 5,000-6,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बासमती और चावल की अन्य किस्मों की खेती की जा रही है। बीते दो सालों से उज्जैन जिले के कई गांवों में किसानों का रुझान बासमती और चावल की दूसरी किस्मों की खेती के प्रति काफी बढ़ा है। उज्जैन से सटे देवास जिले के किसान भी चावल की खेती कर रहे हैं। इंदौर जिले के किसानों ने भी इस साल पहली बार चावल की खेती की है। जहां उज्जैन और देवास जिले के किसान चावल की सफल खेती कर रहे हैं। वहीं इंदौर जिले के किसानों को यह नवाचार महंगा पड़ गया। इंदौर में बीते कुछ सालों से सोयाबीन की खेती में हो रहे हैं नुकसान को देखते हुए किसानों की दिलचस्पी चावल की खेती की तरफ बढ़ी थी। हालांकि इस नवाचार में किसानों को सफलता नहीं मिली और हजारों बीघा की फसल बर्बाद हो गई और किसानों ने समय से पहले ही फसल काटनी पड़ी तो कई जगह पशुओं को खिलाना पड़ा।

उज्जैन में कम पानी में पकने वाली किस्मों ने किया आकर्षित

दो साल से बासमती और दूसरी किस्मों की खेती कर रहे हैं उज्जैन जिले की घटिया तहसील के पिपलिया हामा गांव के प्रगतिशील किसान अश्विनी सिंह चौहान बताते हैं कि लगभग 100 एकड़ में धान की रोपाई की है। जिसमें बासमती की पूसा 1509, जवाहर 206 और एमटीयू 1010 किस्में शामिल हैं। जून-जुलाई माह में सीड्रिल से सीधे बोवनी कर दी जाती है। जवाहर 206 किस्म से चिवड़ा और इडली डोसा जैसे उत्पादों को तैयार किया जाता है। इस किस्म को जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर ने ईजाद किया था। 120 दिनों में यह किस्म पक जाती है।

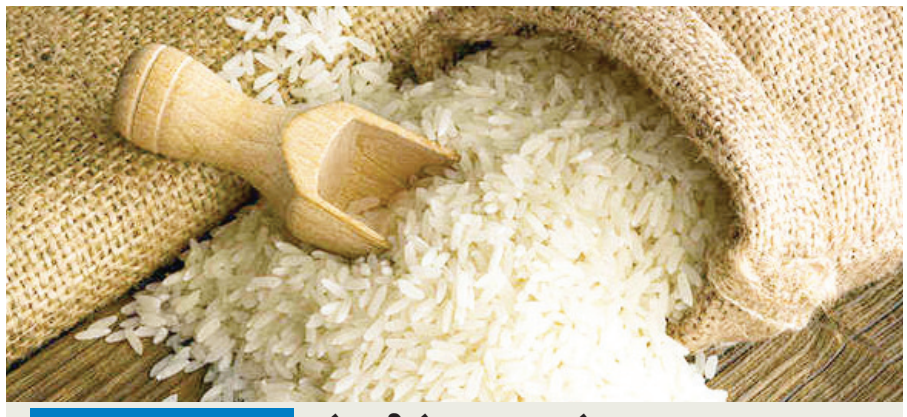

इंदौर जिले के किसानों को नुकसान

इंदौर जिले के किसानों का यह नवाचार असफल रहा है। सांवेर तहसील के बारोद गांव के किसान अर्जुन आंजना बताते हैं कि उज्जैन जिले के किसानों की देखा-देखी उन्होंने इस साल 40-45 एकड़ में धान की बोवनी की थी। लेकिन समय पर बारिश नहीं होने की वजह से उनकी फसल खराब हो गई। इसके चलते फसल को समय से पहले ही काटना पड़ा। अर्जुन अब अपने खेतों में आलू की बोवनी करेंगे। देपालपुर के पाल्या गांव के किसान विजेन्द्र पटेल के पास 30 एकड़ जमीन में धान बोया गया था, लेकिन खरपतवार की वजह से फसल खराब हो गई।

सोयाबी में घाटा, धान में फायदा

उज्जैन जिले की घटिया तहसील के ककदवाली गांव के किसान अभिजीत सिंह ने एक चर्चा के दौरान बताया कि उनके पास 25 एकड़ जमीन है। कुछ सालों से सोयाबीन की फसल लगातार खराब हो रही है। इस वजह से इस बार 8 एकड़ में धान की बोवनी की है। अभी फसल में बालियां आने लग गई हैं। उन्हें उम्मीद है कि धान का अच्छा उत्पादन होगा। उन्होंने धान की जवाहर 206 किस्म की बोवनी की है। जिसमें प्रति बीघा 15 से 17 किलोग्राम बीज की जरुरत पड़ती है।

सुप्रीम को दिखाई राह

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग देने वाली याचिका पर पुनः सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने जीआई टैग की मांग इस तर्क पर की है कि यहां परंपरागत तरीके से बासमती चावल की खेती होती है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि एमपी में उत्पादित होने वाला बासमती पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादित बासमती की तुलना में बेहतर है। भारत बासमती का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत से इराक, ईरान, सउदी अरब, यूएई, कुवैत, यमन, यूके, यूएसए, कतर ओमान समेत कई देशों में बासमती निर्यात होता है।

उज्जैन जिले के कुछ किसान बीते दो सालों से चावल की खेती के प्रति रुझान दिखा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल धान का रकबा बढ़ा है। किसानों ने मध्य अवधि की किस्में लगा रखी है। मालवा में कई बार जून-जुलाई मानसून के समय लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। ऐसे में किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था होना आवश्यक है। यदि किसानों के पास शुरुआती फसल में पानी देने की सुविधा है तो सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है।
डीएस तोमर, कृषि वैज्ञानिक, उज्जैन कृषि विज्ञान केंद्र

मप्र चार लाख किसान कर रहे बासमती की खेती

कृषि विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश सालाना 59,238 मीट्रिक टन बासमती निर्यात करता है, जो बेहतर क्वालिटी का होता है। बासमती को भौगालिक पहचान दिलाने वाली कानूनी लड़ाई में कई बार मध्य प्रदेश के पक्ष में फैसला आ चुका है, बावजूद एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) की अपील और विरोध के कारण मामला अटकता रहा है। बासमती की खेती से मध्य प्रदेश के तकरीबन 4 लाख किसान जुड़े हुए है, ऐसे में सरकार का कहना है कि इन किसानों के हित और बासमती की गुणवत्ता को देखते हुए जीआई टैग दे दिया जाए।

कौड़िया गांव में कृषक महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण

टीकमगढ़।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, वैज्ञानिक डॉ. आईडी सिंह और जयपाल छिगारहा द्वारा विगत दिवस गांव कौड़िया में कृषक महिलाओं को पोषण वाटिका के विकास एवं उसके महत्व पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कृषक महिलाओं को पोषण वाटिका में वर्षभर लगने वाली सब्जियों से अवगत कराया गया और पोषण वाटिका में आम, अमरूद, नींबू, आंवला, पपीता, शीताफल व मुनगा आदि के कम से कम एक-एक पौधा लगाने की सलाह दी गई। पोषण वाटिका परिवार सदस्यों के आधार पर उसका आकार तय कर सकते हैं। खरीफ मौसम में पोषण वाटिका में सब्जियां-मिर्च, बैगन, टमाटर, भिंडी, लौकी, तोरई, खीरा, बरबटी, अदरक, हल्दी एवं अरबी आदि लगा सकते हैं। रबी मौसम में गोभियां, मटर, मूली, गाजर, पालक, धनियां चैलाई, भाजी, आलू, प्याज, लहसुन और जायद मौसम कददूवर्गीय सब्जियां, लौकी, कददू, तोरई, करेला, भिंडी आदि सब्जियां इसी क्रम में लगाने से वर्ष भर ताजी एवं स्वच्छ सब्जियां प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही जैव उर्वरक एवं जैविक कीटनाशक दवाएं डालकर स्वास्थ्य वर्धक सब्जियां पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार फलदार पौधे लगाकर पूरे परिवार ताजे व स्वच्छ फल खिलाकर कुपोषण मुक्त मप्र बनाने में अहम भूमिका सिद्ध होगी। महिलाओं को फलदार पौधे और सब्जियों के बीज वितरण किए गए।

42.16 लाख अपात्र किसानों से सरकार वसूलेगी 2992.75 करोड़

पीएम सम्मान निधि पाने वाले फर्जी किसानों पर अब कसा शिकंजा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त सरकार ने किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। हालांकि, अभी भी कई किसानों के खाते में किस्त के 2000 रुपए नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा कई अपात्र किसानों ने योजना का लाभ ले लिया है। सरकार ने इन अपात्र किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मप्र सहित कई राज्य सरकारों ने गलत तरीके से योजना का फायदा लेने वालों को रिकवरी नोटिस जारी कर वसूली शुरू कर दी है।

-प्रदेश में 195.9 करोड़ की वसूली, श्योपुर में 10 हजार अपात्र मिले

संवाददाता, भोपाल

अपात्र किसानों में सबसे ज्यादा फर्जी आधार वाले लाभार्थी हैं। इनकी संख्या 3.86 लाख है। इसके बाद 2.34 लाख से ज्यादा किसान टैक्सपेयर्स होने के कारण पीएम किसान योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 32 हजार से ज्यादा मृत किसानों के खाते में किस्त की रकम भेजी जा रही है। सरकार ने देशभर में 42 लाख से ज्यादा अपात्र किसानों की पहचान की है। इनके खाते में अब तक 2,900 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। देशभर में ऐसे 42.16 लाख किसानों से 2992.75 करोड़ रुपए वसूलने का काम प्रदेश सरकारों के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। मध्यप्रदेश में अपात्र घोषित किए गए किसानों से 195.9 करोड़ की वसूली की जा रही है। इसमें 10 हजार किसान श्योपुर जिले के शामिल है। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को छह हजार रुपए सालाना दिया जाता है। इसमें ऐसे छोटे किसानों को शामिल किया गया है, जिनके पास जमीन कम है, जिनके रिश्तेदार सरकारी विभागों में बड़े कर्मचारियों व अधिकारियों के पदों पर आसीन नहीं हैं। आयकर दाता किसानों को भी इस लाभ से वंचित रखा है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे अपात्र किसानों ने ना सिर्फ आवेदन कर लिए बल्कि पहली किस्त के रूप में दो हजार रुपए ले भी लिए, जो योजना के लिए पात्र नहीं थे। सॉफ्टवेयर से माध्यम से हुई जांच में यह गड़बड़ी पकड़ी गई। अब सरकार ने फर्जी किसानों से वसूली की कार्रवाई कर रही है।

मप्र में 195.9 करोड़ की होगी वसूली

मप्र में 195.9 करोड़ रुपए की वसूली के लिए केंद्र सरकार ने पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से भू-अभिलेख आयुक्त ज्ञानेश्वर बी पाटील ने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वह पीएम सम्मान निधि योजना में अपात्र चिन्हित हुए किसानों से उनके हाथों में डाली गई राशि वसूलने की कार्रवाई करें। खास बात यह है कि अन्य प्रदेशों में तो किसानों से एक ही किस्त के रूप में दो हजार वसूल किए जाने हैं, लेकिन मप्र में यह रकम दोगुनी वसूल होगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सीएम सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 4 हजार अपनी तरफ से किसानों के खातों में डालती है। सरकार की ओर से एक किस्त के रूप में दो हजार किसानों के खातों में डाले जा चुके हैं।

भोपाल के 14 ग्राम ओडीएफ प्लस घोषित

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया के मुख्य आतिथ्य में भोपाल जिले के 14 ग्राम पंचायत ओडीएफ प्लस (खुले में शौचमुक्त) घोषित कर दिया है। भोपाल जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में थर्ड जेंडर संजना भोपाल की स्वचछता की ब्रांड एम्बेसेडर के साथ 14 ग्रामों की स्वच्छता दूत महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है। भोपाल जिले की 14 गांव जिनमें फन्दा जनपद पंचायत की जनपद पंचायत ईंटखेड़ी सड़क के ग्राम घीसीपुरा, मंडला के ग्राम कल्यानपुर, निपानिया सूखा के ग्राम रोजीबेग, तारासेविनया के ग्राम पृथ्वीपूरा, सरवर के ग्राम मित्तूखेड़ी, ईंटखेड़ी छाप के ग्राम खामलाखेडी, झिरनिया के ग्राम दौलतपर ठिकरिया, खजूरी सड़क के ग्राम खेतलाखेड़ी, बकानिया के ग्राम बकानिया, मेंडोरी के ग्राम मंडोरा, बैरसिया जनपद पंचायत की जनपद पंचायत दमीला फन्दा जनपद पंचायत की जनपद पंचायत दमीला के ग्राम दमीला, गनीयारी, भमोरी, शेषापुरा, कनेरा, बैरागढ़ के ग्राम बैरागढ़, बैरागढ़ के ग्राम परवारिया, गरेठिया दांगी के ग्राम सागोनीखुर्द, रतुआ रतनपुर के ग्राम सागोनी जोरा शामिल हैं। केन्द्र सरकार ने 01 अप्रैल 2020 से स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण प्रारंभ किया है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण प्रारंभ किया है । जिसका प्रमुख उदेश्य वर्ष 2024 तक ग्रामों में अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्वच्छता को टिकाउ बनाने में योगदान देना है। जिससे ग्रामीण आबादी का जीवनस्तर बेहतर हो सके। 202 ग्रामों में से 14 ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। शेष 186 ग्रामों को वर्ष 2022 मार्च तक ओडीएफ प्लस करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओडीएफ प्लस ग्राम जहां खुले में शौच से मुक्त वातावरण का निरतरता को सुनिश्चित कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन की ओर कदम बढ़ाया गया है।

राज्य सरकार असली हकदार की करेगी खोज, गड़बड़ियों को सुधारने अब चलाएगे अभियान

प्रदेश में नौ लाख खसरों में भूमि स्वामी 'लापता'

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में लगभग नौ लाख खसरे ऐसे हैं, जिनमें यह दर्ज ही नहीं है कि भूमि का मालिक कौन है। भूमि सरकारी है या फिर निजी। इसी तरह कई गांव के नक्शे और खसरे में भूखंडों की संख्या में काफी अंतर है। राजस्व रिकॉर्ड में इस तरह की गड़बड़ियों को सरकार अब अभियान चलाकर ठीक करेगी। इसके लिए राजस्व विभाग ने कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी के स्तर पर सर्वे कराकर भूमि संबंधी रिकार्ड को दुरुस्त करने का कार्यक्रम बनाया है। प्रदेश में भू-अभिलेखों का संधारण भूलेख पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। खसरा, नक्शा, खतौनी, अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि डिजिटल हस्ताक्षर से उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए खसरों में जो भी परिवर्तन होते हैं, उसका भू-अभिलेखों में दर्ज होना अनिवार्य है।

सर्वे कर दर्ज करेंगे नाम

दरअसल, राजस्व विभाग ने जब पड़ताल की तो पता लगा कि नौ लाख खसरों में भूमि स्वामी का नाम ही नहीं है। उधर, निजी भूमि का नामांतरण आसानी हो जाता है, पर शासकीय भूमि की प्रक्रिया जटिल है। इसके मद्देनजर तय किया गया है कि सर्वे कराकर प्रत्येक खसरे में भूमि स्वामी का नाम दर्ज किया जाएगा।

सवा दो लाख खसरों का वर्गीकरण ही नहीं

प्रदेश में सवा दो लाख से ज्यादा खसरे ऐसे भी हैं, जिनका वर्गीकरण ही नहीं है। ये शासकीय हैं या निजी, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसमें सुधार की प्रक्रिया चल रही है। खसरे का वर्गीकरण शासकीय, निजी या अन्य में किया जाएगा। इसके साथ ही भूमि स्वामी में अब शासकीय, संस्था, आधिपत्य किसान, वक्फ संपत्ति, शासकीय पट्टेदार, भूदानधारी, देवस्थान, अस्थाई पट्टेदार, आबादी, सेवा खातेदार आदि के रूप में स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

जिन नामों में अशुद्धियां हैं, उनमें सुधार किया जाएगा। इसके लिए आवेदन लेकर राजस्व न्यायालय में आदेश पारित किए जाएंगे। भूलेख पोर्टल पर जानकारी दर्ज होगी और फिर खसरे को अंतिम रूप दिया जाएगा। यदि खसरे में किसी तरह भी तरह की अशुद्धि होती है तो साफ्टवेयर उस खसरे को प्रदर्शित ही नहीं करता है। कई खसरों में भूमि स्वामी के नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं।

ज्ञानेश्वर पी पाटिल, आयुक्त भू-अभिलेख

कृषि में कीर्तिमान गढ़ता मध्यप्रदेश

कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था से गौरवान्वित मध्यप्रदेश कृषकों को सक्षम और सम्पन्न बनाने के लिए कृत-संकल्पित है। राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लगातार कृषि कल्याणकारी योजनाओं और नवाचारों को बढ़ावा दिया है और किसान हित में ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। इसके सुखद परिणाम प्रदेश की खुशहाली के रूप में आ रहे हैं। अन्नदाताओं में विश्वास बढ़ा है और प्रदेश आत्म-निर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विगत डेढ़ दशक में प्रदेश में बोई जाने वाली अधिकांश फसलों ने उत्पादन तथा उत्पादकता के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

सोयाबीन की फसल तो मध्यप्रदेश की पहचान के साथ किसानों की भी ताकत बन गई है। यह खरीफ मौसम में प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। इसके अलावा अरहर, मूंग, उड़द, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदों, कुटकी, तिल, कपास आदि के उत्पादन और खरीदी में देश में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। वहीं रबी में गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, गन्ना, अलसी आदि प्रमुख फसलें हैं। इनमें गेहूं का रकबा सर्वाधिक है। गेहूं की उत्पादकता के लिए किए गए प्रयासों से इसका क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता भी तेजी से बढ़ रही है। कपास तथा गन्ना फसल भी हमारी प्रमुख नकद फसलें हैं। कृषि क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ सम्मान कृषि कर्मण को मध्यप्रदेश द्वारा लगातार जीतने का गौरव हासिल करना वास्तव में अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत और किसान-कल्याणकारी योजनाओं का ही परिणाम है। कृषि हितों को लेकर विभिन्न आयामों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य में खरीदी से प्रदेश के किसानों में और ज्यादा खुशहाली आएगी और उनका विश्वास बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन वर्ष 2020-21 एवं विपणन वर्ष 2021-22 के लिए पंजीकृत कृषकों से फसल उपार्जन के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन वर्ष 2020-21 एवं विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष में उपार्जन के लिए मंजूरी दी गई है। अब तक समर्थन मूल्य पर 3 लाख 29 हजार मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन किया जा चुका है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना हमारी प्राथमिकताओं में है। गेहूं उपार्जन में प्रदेश अब अग्रणी राज्य में शुमार हो गया है। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई-ट्रेडिंग का प्रावधान और किसानों को उपार्जन केन्द्र के साथ ही मंडी के अधिकृत निजी खरीदी केन्द्र और सौदा-पत्रक व्यवस्था के माध्यम से भी फसल बेचने की सुविधा प्रदान की गई। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से भारत के ग्रामीण समाज का विकास और प्रगति से सीधे जुड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत का आम किसान गांवों में रहता है, उसके लिए खेती और उसकी मिट्टी आस्था का सवाल है। योजना में ट्रायल के तौर पर जिन 6 राज्यों का चयन किया गया है, उसमें मध्यप्रदेश भी है। पूरे प्रदेश के किसान इस योजना से अधिक से अधिक लाभान्वित हो, इसके लिए हम लगातार समन्वय और प्रशासनिक सुदृढ़ता से काम कर रहे है। योजना से लाभान्वित प्रथम हितग्राही रामभरोस विश्वकर्मा प्रदेश के हरदा जिले का निवासी है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देश में कृषि अधोसंरचना में सुधार और सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है। इसमें मध्यप्रदेश को साल 2020-21 में 7500 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके उपयोग में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आधुनिक मंडियों की स्थापना, फूड पार्क, शीत गृहों की श्रृंखला स्थापित करने के साथ साइलोस एवं वेयर हाउस के निर्माण को मिशन मोड में प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान अपनी उपज को एमएसपी के स्थान पर एमआरपी पर बेचने के लिए सक्षम होंगे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि मप्र इसमें अग्रणी है। नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फायनेंसिंग फेसिलिटी पोर्टल बहुत ही कम समय में एआईए पोर्टल पर 2,352 आवेदन आए हैं। इनका लगातार सत्यापन किया जा रहा है और 618 करोड़ का भुगतान भी बैंकों द्वारा कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारिक तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच तय की जा सके। साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनेटिक मापदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। योजना के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में अनाज और अन्य फसलों के भंडारण के लिए आधुनिक तकनीकी से युक्त भंडार गृहों के निर्माण कर इसे ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6-6 हजार रुपए तो मिल ही रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान-कल्याण सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर किसानों को मप्र शासन की ओर से प्रतिवर्ष 4 हजार दो बराबर किश्तों में दिये जाना शुरू किया गया है। इस प्रकार किसानों को अब कुल 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं पर भी प्राथमिकता से कार्य करवाये जा रहे हैं। इन कार्यों से प्रदेश में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। खेती में उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए मध्यप्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर अंतर्गत लगातार काम किया जा रहा है। खेती को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना ही डिजिटल कृषि कहलाता है। मध्यप्रदेश ने डिजिटल एग्रीकल्चर यानि फसलों की पैदावार बढ़ाने और खेती को सक्षम एवं लाभदायक बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और सेवाओं का इस्तेमाल लगातार बढ़ाया है। यह कृषकों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो रहा है।

देश के उद्योग व्यापार जगत को चाहिए चेतना

यह निराशाजनक है कि भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे का अंतर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि, लद्दाख सीमा पर तनाव कायम रहने और कोविड महामारी का प्रसार होने के कारण एक ऐसा माहौल बना था जिसमें चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने की मुहिम तेज हुई थी। उम्मीद की जाती थी कि यह मुहिम रंग लाएगी, लेकिन प्रारंभ में मामूली सफलता के बाद कुछ विशेष हासिल नहीं हो सका। दुर्भाग्य से ऐसा तब हुआ जब भारत सरकार की ओर से देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक अभियान भी छेड़ा गया। इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य चीनी आयात को कम से कम करना था। माना जा रहा था कि सरकार के इस अभियान और देश-विदेश में चीन विरोधी भावनाओं के चलते उसका उल्लेखनीय असर होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। विडंबना यह रही कि भारत की तरह अन्य देश भी चीनी आयात पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर सके। दुनिया के अन्य देश अपनी इस नाकामी पर कुछ भी सोचें, भारत के लिए यही उचित होगा कि वह चीन से होने वाले आयात को कम करने के लिए नए सिरे से सक्रिय हो। यह सक्रियता तभी प्रभावी होगी, जब भारत के उद्योग यह समझेंगे कि चीन पर निर्भरता उनके अपने हितों के प्रतिकूल है। कायदे से होना यह चाहिए था कि भारत के छोटे-बड़े उद्योग एवं व्यापार जगत उन वस्तुओं का निर्माण देश में ही करने के लिए कमर कसता, जिन्हें वह चीन से मंगाता था। यह ठीक है कि चीन से तमाम वस्तुओं को मंगाना सस्ता पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत का उद्योग व्यापार जगत अपने हित किसी और देश के पास गिरवी रख दे। यह सही समय है कि उद्योग व्यापार जगत के साथ वित्त मंत्रलय, वाणिज्य मंत्रलय और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रलय ऐसी कोई रूपरेखा बनाएं, जिससे भारतीय उद्यमी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम साबित हों। उचित यह होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की नए सिरे से समीक्षा हो। यह इसलिए भी आवश्यक है कि जब तक व्यापार का पलड़ा चीन के पक्ष में झुका रहेगा, तब तक वह सीमा विवाद और अन्य अनेक मसलों पर अपने अड़ियल रवैये का परित्याग नहीं करने वाला। भारत सरकार और देश के उद्योग व्यापार जगत को इसलिए भी चेतना चाहिए, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड डूबने की कगार पर है। इसके चलते चीनी अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में फंसने की जबरदस्त आशंका उभर आई है। इतना ही नहीं, यह भी अंदेशा पैदा हो गया है कि चीन में जो आर्थिक संकट आकार ले रहा है वह विश्व अर्थव्यवस्था को कुछ उसी तरह प्रभावित करने का काम कर सकता है, जैसे अमेरिका के लीमैन ब्रदर्स संकट ने किया था।

कृषि निर्यात में 22 फीसदी का इजाफा

पिछले साल की अपेक्षा भारत से विदेश जाने वाले कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई है। एपीडा बास्केट में उत्पादों का निर्यात अप्रैल-अगस्त (2020-21) के 6,485 मिलियन डॉलर की तुलना में चालू वित्त वर्ष (2021-22) के पहले पांच महीनों के दौरान बढ़कर 7,902 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के उत्पादों के समग्र निर्यात ने 2021 के अप्रैल-अगस्त के दौरान डॉलर के हिसाब से पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कृषि ऊपज की निर्यात संभावनाओं को व्यापक रूप से बढ़ावा देते हुए, भारत ने 2021-22 (अप्रैल-अगस्त) में कृषि संबंधी तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 21.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। एपीडा के उत्पादों का कुल निर्यात 2020 के अप्रैल-अगस्त के 6,485 मिलियन डॉलर की तुलना में 2021 के अप्रैल-अगस्त के दौरान बढ़कर 7,902 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। डब्ल्यूटीओ के व्यापार मानचित्र के अनुसार, वर्ष 2019 में 37 बिलियन डॉलर के कुल कृषि-निर्यातों के साथ भारत विश्व रैंकिंग में नौवें स्थान पर है। चावल के निर्यात ने 13.7 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज कराई और यह 2020 के अप्रैल-अगस्त के 3,359 मिलियन डॉलर की तुलना में 2021 के अप्रैल-अगस्त में 3,820 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। त्वरित अनुमानों के अनुसार, ताजे फलों तथा सब्जियों ने डॉलर के हिसाब से 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई, जबकि सीरियल्स प्रीपरेशंस जैसे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों और विविध प्रसंस्कृत मदों के निर्यात में 41.9 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गई। अप्रैल-अगस्त 2020-21 में, ताजे फलों तथा सब्जियों का निर्यात 1,013 मिलियन डॉलर के बराबर था जो अप्रैल-अगस्त 2021-22 में 1,075 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। भारत ने चालू वित्त वर्ष (2021-22) के पहले पांच महीनों के दौरान अन्य मोटे अनाजों के निर्यात में 142.1 प्रतिशत की उछाल दर्ज की जबकि मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में 31.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अन्य मोटे अनाजों का निर्यात अप्रैल-अगस्त 2020 के 157 मिलियन डॉलर की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2021 में 379 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया तथा मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात अप्रैल-अगस्त 2020 के 1185 मिलियन डॉलर की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2021 के दौरान 1554 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। काजू के निर्यात में अप्रैल-अगस्त 2021 के दौरान 28.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जो अप्रैल-अगस्त 2020 के 144 मिलियन डॉलर की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2021 में 185 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्यरत एपीडा द्वारा की गई पहलों ने देश को ऐसे समय में यह उपलब्धि हासिल करने में सहायता की है जब अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियों को कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर आने के बाद लगाये जाने वाले प्रतिबंधों के कारण भारी झटका लगा था। कृषि संबंधी एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में यह वृद्धि विभिन्न देशों में बी 2 बी प्रदर्शनियों के आयोजन, भारतीय दूतावासों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा उत्पाद विशिष्ट तथा सामान्य विपणन अभियानों के माध्यम से कृषि संबंधी एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए एपीडा की विभिन्न पहलों के कारण संभव हो पाई है। एपीडा ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों पर और अमेरिका के साथ हस्तशिल्प सहित जीआई उत्पादों पर वर्चुअल तरीके से क्रेता-विता बैठकों का आयोजन करने के द्वारा भारत में पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों (जीआई) वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। एपीडा निर्यात की गई प्रमुख कृषि संबंधी कमोडिटीज के जीआई उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए संभावित आयातक देशों के साथ वर्चुअल क्रेता-विता बैठकों (वीबीएसएम) का आयोजन करने की पहल लगातार कर रहा है। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का निर्बाधित गुणवत्ता प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए एपीडा ने उत्पादों तथा निर्यातकों के एक व्यापक रेंज को परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत भर में 220 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है।

बेस्ट टूरिज्म विलेज अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट

देश-विदेश के सैलानियों का जुट रहा हुजूम

ओरछा में देश का सबसे सुंदर गांव

आकर्षण का केंद्र एमपी के दो गांव

मध्यप्रदेश के दो गांव इन दिनों आम लोगों के साथ विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जहां एक ओर विश्व पर्यटन के नक्शे पर ओरछा का एक गांव अपनी पहचान बनाने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मंडला जिले प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के साथ अब एक और पर्यटन स्थल पर्यटकों की पसंद बन चुका है। ये है अजगर दादर यानी अजगरों का पूरा गांव या कहें पूरी एक बस्ती।

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश का ओरछा जिला विश्व के पर्यटन नक्शे पर एक बार फिर नई पहचान बनाने जा रहा है। ओरछा के पास लाड़पुरा गांव है। ये गांव देश के तीन सबसे अच्छे पर्यटन ग्रामों में शामिल होने जा रहा है। विश्व पर्यटन संगठन के बेस्ट टूरिज्म विलेज अवॉर्ड के लिए इस गांव का नामांकन हुआ है। इसे लेकर गांव के लोगों के बीच जबरदस्त खुशी का माहौल बना हुआ है। यहां की आबोहवा, प्राकृतिक सौंदर्य, रहन-सहन और खान-पान पर्यटकों को यूं ही अपनी ओर खींच लाता है। लाड़पुरा गांव की जनसंख्या 1110 है। इनमें से 80 प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं। लोग इसलिए खिंचे चले आते हैं, क्योंकि, यहां प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार है। जंगल, तालाब और पहाड़ तो हैं ही, साथ ही लोक कला और लोक संस्कृति भी निराली है। यहां पर्यटकों को चौसर, गुल्ली-डंडा और कबड्डी जैसे कई खेल खिलाए जाते हैं। शाम को पर्यटक बुंदेली लोकगीत, राई-गोटे और फाग जैसे कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। लाड़पुरा की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन विभाग को बधाई दी है। उनका कहना है कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारा प्रदेश नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अद्भुत स्थापित कला का धनी है। इस गांव का प्राकृतिक सौंदर्य और खानपान पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है।

अवॉर्ड के लिए देश के तीन गांवों का किया गया चयन

गौरतलब है कि पूरे देश में इस अवॉर्ड के लिए मात्र 3 गांवों का चयन किया गया है। इनमें मेघालय का कांति कांगतोंग गांव, तेलंगाना का पंचम्पेली गांव और प्रदेश का लाडपुरा गांव शामिल हैं। इसे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। ओरछा से करीब 8 किमी दूर बसे इस गांव की खासियत है कि है कि महिलाएं यहां आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। कई महिलाएं ई-रिक्शा चलाती हैं और परिवार और गांव के विकास में मदद करती हैं। इस गांव की प्रसिद्धी से यहां टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। इससे यहां लोगों की जिंदगी बदल रही है।

आज तक किसी ग्रामीण को काटा तक नहीं

मंडला के एक गांव में अजगरों की बस्ती

इधर, मंडला में प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के साथ अब एक और पर्यटन स्थल पर्यटकों की पसंद बन चुका है। ये है अजगर दादर यानी अजगरों का पूरा गांव या कहें पूरी एक बस्ती। यहां हजारों की तादाद में अजगर हैं।

अजगरों की ये बस्ती कान्हा के बफर जोन से लगे अंजनिया वन परिक्षेत्र के ककैया गांव में है। 1926 में आयी बाढ़ में ये जगह पोली हो गयी थी। तब से जीव जन्तुओं ने यहां अपना डेरा जमा लिया। 2014-15 में वन विभाग के प्रयास से ये जगह लोगों की नजर में आई। हजारों अजगरों को यहां एक साथ रेंगते देखा जा सकता है। न गांव वाले इन्हें परेशान करते हैं और न ही गांव वालों को कभी इन्होंने काटा।

कान्हा के बाद अजगर दादर- अजगर दादर मंडला जिले का दूसरा प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। दुनिया में प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के कारण वन्य प्राणि प्रेमियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। अब इस अजगर दादर भी पर्यटकों में काफी उत्सुकता पैदा कर रहा है।

अजगर देख सिट्टी-पिट्टी गुम

पर्यटक हमेशा नई और खतरनाक रोमांचक चीजें देखने के शौकीन होते हैं। इसलिए मंडला आते हैं हैं। पर्यटकों को यहां एक रोमांच का अनुभव होता है जिसे देखते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। यहां अजगरों को खुले आम आराम फरमाते देखा जा सकता है और वो भी एक दो नहीं बल्कि झुंड के झुंड नजर आते हैं।

सर्दी में सेंकते हैं धूप

अजगर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इस स्थान पर ठंड के मौसम में बड़ी संख्या में अजगर धूप सेंकते हुए दिख जाते हैं। गांव वाले इन्हें परेशान नहीं करते और न ही इन्होंने कभी गांव वालों को डसा। यहां अजगर और इंसानों के बीच अजीब रिश्ता है। गांव वाले इन अजगरों की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील हैं।

1926 की बाढ़

1926 में यहां भीषण बाढ़ आयी थी और ये स्थान पोला हो गया था। बस तभी से यहां तरह तरह के जीव जंतु रहने लगे। इन्हीं पोले स्थानों को अजगरों ने भी अपना निवास बना लिया। यह स्थान 2014-2015 के आस-पास वन विभाग के प्रयासों से लोगों की नजर में आया है। कान्हा पार्क की तरह इस जगह के बारे में ख्याति फैल रही है और पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है।

कृषि मंत्री कमल पटेल बोले-मंडियों को बनाएं सर्वसुविधा युक्त, कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 137वीं बैठक संपन्न

किसानों की सुविधाओं में नहीं होनी चाहिए कोई कमी

» मंडियों में अब आउटसोर्स में रखे जाएंगे अधिकारी-कर्मचारी

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडियों को अत्याधुनिक सुविधायुक्त कर किसानों को अधिक से अधिक मंडियों की ओर कृषि उपज विक्रय करने के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। किसी भी स्थिति में किसानों को मंडियों में असुविधा न हो। इस के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। यह बात प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 137वीं बैठक के दौरान कही। संचालक मंडल की बैठक में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी, कृषि विभाग के अपर संचालक एससी सिंगादिया, संयुक्त आयुक्त प्रतिनिधि पंजीयक सहकारी संस्थाएं बीएस शुक्ला, मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक विकास नरवाल मौजूद रहे। प्रबंध संचालक ने कृषि मंत्री कमल पटेल और अपर मुख्य सचिव का स्वागत किया। संचालक

मंडल की बैठक में तय विषयों पर चर्चा के बाद मंडी बोर्ड की 136वीं बैठक की कार्रवाई विवरण की पुष्टि की गई। मंडी बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय पर पालन प्रतिवेदन पेश किया गया। राज्य मंडी बोर्ड सेवा एवं अन्य विभागों से मंडी बोर्ड मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय या मंडी समितियों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रस्तावित स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1988 में लागू करना और मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड/कृषि उपज मंडी समितियों के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन को आउटसोर्स से रखने की अनुमति दी गई। सीधे खलिहान और घर से किसानों की उपज विक्रय व भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एमपी फार्मगेट एप विकसित एवं संचालन करने की मंजूरी दी गई। ई-अनुज्ञा, ई-मंडी, ई-नाम, एमपी फार्मगेट एप, एगमार्कनेट पोर्टल, ई-आफिस, ई-टेंडरिंग, एनपीएस,रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन, एचआर माड्यूल प्रापर्टी मेनेजमेंट मॉड्यूल,जीपीएमएस इत्यादि के संचालन के लिए परामर्शी एवं वेब/एप डेव्हलपर की सेवाएं प्रदान करने के कार्य की स्वीकृति दी गई। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत मंडी बोर्ड के लक्ष्य व प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कृषि उपज मंडी प्रांगणों में आवक और आय में वृद्धि करने के लिए कृषि उपज के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंध के लिए सुविधएं विकसित करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी ने भी मंत्रीजी के निर्देशों का अक्षरशः पालन किए जाने के निर्देश दिए।

-केंद्रीय कृषि मंत्री बोले-हम किसानों के हित में प्रतिबद्ध

मप्र को कृषि का मॉडल राज्य बनाएंगे

राजधानी भोपाल पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा की मप्र को कृषि के क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाना है। इस दिशा में केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। वर्ष 2003 के पहले भी मध्य प्रदेश में खेती तो होती थी पर देश में कहीं भी चर्चा नहीं होती थी। आज मध्य प्रदेश की तुलना पंजाब और हरियाणा से होती है। एक समय में मध्य प्रदेश देशभर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने में अव्वल था, लेकिन अब कृषि सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के हित में प्रतिबद्ध रहे हैं। सात सालों में कृषि के क्षेत्र में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए जो आम किसान के लिए लाभप्रद है।

» पीएम किसानों के जीवन में सुधार लाने उठा रहे कदम

» कृषि अधोसंरचना निधि से किसानों को फायदा होगा

भोपाल।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भोपाल के मिंटो हाल में जनकल्याण और सुराज अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में पूरा देश खड़ा है। जो लोग इसका विरोध कर रहे है अगर वे नए प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। किसी किसान ने सम्मान निधि की मांग नहीं की थी पर प्रधानमंत्री की सोच है कि छोटे क्षेत्र (रकबा) वाले किसानों की सहायता होनी चाहिए। कृषक उत्पादक संगठन के गठन और कृषि अधोसंरचना निधि से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसान ही उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। जब उसकी जेब में पैसा होगा तभी बाजार चलेंगे।

खेती की लागत में कमी लाना होगा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार 10 हजार हजार नए एफपीओ, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों के साथ ही फूड प्रोसेसिंग उद्योग व निर्यात को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रही है। इन उदेश्यों को सार्थक करने के लिए खेती की लागत में कमी लाना होगा, टेक्नालाजी का उपयोग बढ़ाना होगा, कृषि क्षेत्र का डिजिटलाइजेशन करना होगा, सुरक्षा कवचों का फायदा किसानों को दिलाना होगा, इसकी जिम्मेदारी शिक्षित युवाओं की भी है।

मूंग में किसानों को हुआ फायदा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि लागत घटाने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने से किसानों को प्रति क्विंटल तीन हजार रुपए का फायदा हुआ। उन्होंने किसानों को फसल चक्र परिवर्तन करने का सुझाव दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि समर्थन मूल्य पर चना, मसूर, सरसों और मूंग खरीदकर दस हजार करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद भी किया। इस दौरान बीज ग्रामों का शुभारंभ, कृषक उत्पादक संगठनों का गठन, बीज के मिनी किट का वितरण और कृषि अधोसंरचना निधि के तहत राशि का वितरण किया गया।

कोदो, कुटकी को विदेश में बेचेगी सरकार

» वाणिज्य उत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा

» उत्पादों को विदेशों में बेचने बनेगी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल

भोपाल। मप्र में उत्पादित होने वाले कोदो, कुटकी और एक कली वाले लहसुन जैसे लोकल प्रोडक्ट अब विदेश में बिकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मप्र के उत्पादों को विदेशों में बेचने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन एक सप्ताह में हो जाएगा। यह काउंसिल एक जनवरी से लोकल प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजने का काम शुरू कर देगी। खास बात यह है कि इस काउंसिल में एक्सपोर्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। शिवराज ने कहा कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, उसका समाधान खोज रहे हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग बढ़ाने होंगे। हम कई तरह के उत्पाद एक्सपोर्ट करेंगे। एक जनवरी से निर्यात शुरू करने का लक्ष्य है। शहडोल में कोदो कुटकी, नीमच में एक कली का लहसुन का निर्यात कर सकते हैं। हम जरूरत के साथ एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामान बनाएं। हम आज भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर ताइवान की तरह करना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि हमारी ग्रोथ हो रही है, पर एक्सपोर्ट क्वालिटी पर काम करना है। एक हफ्ते में काउंसिल गठित हो जाएगी, ताकि निर्यात से जुड़ी छोटी-छोटी तकनीक पर ध्यान दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट का सर्वे जरूरी है। यह काम सरकार और बाजार, दोनों को मिल कर करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उद्योगों को बनाए रखना होगा। हर जिले में एक्सपोर्ट कमेटी बनाएंगे।

-उद्यानिकी विभाग के अफसरों का चौंकाने वाला करारनामा, -बीज खरीद कर सरकार को एक करोड़ की चपत लगाई

उन्नत किस्म के नाम पर दोगुने रेट में खरीदे प्याज के बीज

भोपाल।

मध्यप्रदेश में उन्नत किस्म के बीजों के नाम पर घटिया और अमानक बीज बेचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन उद्यानिकी विभाग के अफसरों ने उन्नत किस्म के नाम पर दोगुने से अधिक रेट में प्याज के बीज खरीद कर सरकार को करीब एक करोड़ रुपए की चपत लगाई है। मप्र में शिवराज सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी हर हाल में दोगुना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। सरकार के इस लक्ष्य की राह में अफसरों की लालफीताशाही रोड़ा बन रही है। इसका ताजा मामला अभी हाल ही में सामने आया है। प्रदेश में किसानों को प्याज की फसल लगाने के लिए उद्यानिकी विभाग में अफसरों ने प्याज बीज की खरीदी तय दरों से दोगुने दामों में की है। राज्य शासन ने उद्यानिकी नर्सरियों पर उत्पादित प्रमाणित सब्जी बीजों की विक्रय दरें 1100 रुपए प्रति किलो तय कर रखी है, लेकिन उद्यानिकी ने खरीफ प्याज बीज 2300 रुपए प्रति किलो खरीद लिया। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों की पोल खुल गई है। प्याज के बीज खरीदी का मामला धीरे-धीरे गर्माता जा रहा है। अफसरों ने नियमों को ताक पर रखकर एमपी एग्रो की जगह दूसरी संस्थाओं से खरीदी की गई।

मंत्री तक पहुंची शिकायत

दो करोड़ रुपए में 90 क्विंटल प्याज बीज की खरीदी का मामला तूल पकड़ने लगा है। आलम यह है कि नियमों को दरकिनार कर खरीदी करने पर उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह और प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव को शिकायत की गई है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 30 मार्च 2021 से ही खरीफ प्याज पहली बार शामिल किया गया है। उद्यानिकी मंत्री कुशवाह ने बताया प्याज खरीदी को लेकर शिकायतें मिली है।

जांच में खुलेगी भ्रष्टाचार की पोल

विवाद बढ़ने के बाद अब प्याज के बीज खरीदी मामले की जांच शुरू होने जा रही है। यह जांच कई बिंदुओं पर होगी। उद्यानिकी संचालनालय के 29 सितंबर 2020 को जारी पत्र के मुताबिक सब्जी बीज बेचने की दरें(वर्ष 2020-21) में 1100 रुपए प्रतिकिलो है। इसके विपरीत राष्ट्रीयकृत संस्था (एनएचआरडीएफ) के जरिए 2300 रुपए प्रतिकिलो में बिना टेंडर के खरीदी कर दी गई। विवाद के बाद बहाली-कमिश्नर मनोज अग्रवाल से मिलने एमपीएस बुंदेला पहुंचे थे। बुंदेला ने बहाली के लिए कहा, जिस पर आयुक्त ने कह दिया कि कोर्ट के केस वापस लेना होंगे। इस पर विवाद बढ़ गया। बुंदेला ने कहा कि प्याज घोटाले में जेल पहुंचा दूंगा।

काजू 2000 रुपए किलो मिलता है और टुकड़े वाले 200 में मिल जाता है। विभाग ने 2300 रुपए तय किए हैं। ये जरूरी नहीं कि 1100 रुपए किलो में ही खरीदें। हमने अच्छी क्वालिटी का प्याज बीज खरीदा है।

मनोज अग्रवाल, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग

मप्र के अन्य क्षेत्रों के साथ बुंदेलखंड में अपार संभावनाएं

बुंदेलखंड के किसान लहसुन की खेती से होंगे आत्मनिर्भर

टीकमगढ़। लहसुन एक दक्षिण यूरोप में उगाई जाने वाली प्रमुख मसाला फसल है। इसका मुख्यतः उपयोग सब्जियों और आचार में किया जाता है। इसके अलावा लहसुन कई दवाइयों में उपयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीनए फासफोरस और पोटाशियम जैसे स्त्रोत पाए जाते हैं। यह पाचन क्रिया में मदद करता है और मानव रक्त में कोलेस्ट्रोल की मात्रा को कम करता है। बड़े स्तर पर लहसुन की खेती गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महांराष्ट्र, पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में भी लहसुन खेती की अपार संभावनाएं हैं। इससे यहां की किसानों आय भी बढ़ सकती है और वो आत्मनिर्भर भी होंगे।

जलवायु: लहसुन की अच्छी खेती के लिए न अधिक गर्मी का मौसम हो और न ही अधिक ठंड हो। अक्टूबर, नबम्बर का महीना लहसुन की बोवनी के लिए उपयुक्त माना जाता है। लहसुन के लिए तापमान 10.30 और सेंटीग्रेड एवं वर्षा 600.700 एमएम होना चाहिए।

मृदा: लहसुन सभी प्रकार की हल्की से भारी भूमि में उगाया जा सकता है। बलुई दोमट, अच्छी जल निकास वाली, पानी को बांध कर रखने वाली और अच्छी जैविक खनिजों वाली भूमि लहसुन के लिए सर्बोत्तम मानी गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पायी जाने वाली मिट्टी लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त है।

उन्नतशील किस्में: पीजी-17, किस्म के पौधे के पत्ते गहरे हरे रंग के और ऊपर की सतह सफेद और आकर्षित होती है। जिसमें 25.30 कलियां प्रति गांठ होती हैं। यह किस्म 165.170 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 125.135 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

यमुन सफेद-2: इसकी गांठें भी सख्त और सफेद होती हैं और 35.40 कलियां प्रति गांठ होती हैं। इसकी औसतन उपज लगभग 150.175 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

यमुन सफेद-3: गांठे सफेद और आकार में बड़ी होती हैं और 15.16 कलियां प्रति गांठ होती हैं। इस किस्म की औसतन उपज लगभग 175.200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

यमुन सफेद- 4: गांठे सफेद और 20.25 कलियां प्रति गांठ होती हैं। इसकी उपज 200.250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

यमुन सफेद-5: यह फसल पककर कटाई के लिए 150.160 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 150.170 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

भीमा परपल: यह फसल 120.135 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी ऊपरी सतह जामुनी रंग की हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 100.120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

-टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताई विधि

-किसान लहसुन की खेती से कैसे कमाएं अधिक लाभ

वीएल-1: इसकी ऊपरी सतह सफेद रंग की हो जाती है। यह फसल 180.190 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी औसतन पैदावार 125.135 क्विंटल प्रति एकड़ और समतल क्षेत्रों में 100.120 क्विंटल प्रति एकड़ है।

टाइप-56-4: इसमें लहसुन की गांठे छोटी होती हैं और सफेद होती हैं। प्रत्येक गांठ में 25 से 34 पुत्तियां होती हैं। इस किस्म से किसान को प्रति हेक्टेयर 140.160 क्विंटल तक उपज मिलती है।

को-2: इस किस्म में कंद सफेद होते हैं और इस किस्म से किसानों को प्रति हेक्टेयर 150.175 उपज मिलती है।

आईसी-49381: इस किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से किया गया है। इस किस्म से लहसुन की फसल 160 से 180 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म से किसानों प्रति हेक्टेयर 150.200 क्विंटल तक उपज मिलती है।

सोलन: इस किस्म में पौधों की पत्तियां काफी चौड़ी व लंबी होती हैं और रंग गहरा होता है। इसमें प्रत्येक गांठ में चार ही पत्तियां होती हैं और काफी मोटी होती हैं। किसानों प्रति हेक्टेयर 150.190 क्विंटल तक उपज मिलती है।

एग्री फाउंड व्हाइट: लहसुन की इस किस्म में भी फसल 150 से 160 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म से लहसुन की उपज 125.150 क्विंटल प्रति एकड़ होती है।

भूमि की तैयारी: मिट्टी के भुरभुरा होने तक खेत को 3.4 बार जोताई करें। मिट्टी में जैविक खनिजों को बढ़ाने के लिए कम्पोस्ट डालें। खेत को समतल करके क्यारियों बनाएं।

लगाने का समय, दूरी-विधि

लहसुन लगाने का समय सितंबर के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर का अंतिम सप्ताह उपयुक्त है। पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेमी और कतारों में फासला 15 सेमी रखें। लहसुन की गांठों को 3.5 सेमी गहरा और उसका उगने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखें। लगाने के लिए केरा ढंग का प्रयोग करें। गांठों को मिट्टी से ढककर हल्की सिंचाई करें।

कलिका-बीज की मात्र: लहसुन की 225.250 किलोग्राम बीज, कलिका प्रति एकड़ में उचित बीज दर है, क्योंकि इससे कम या ज्यादा बीज लगाने से उपज पर प्रभाव पड़ता है।

सिचाई: वातावरण और मिट्टी की किस्म के आधार पर सिंचाई करें। लगाने के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें और आवश्यकता के आधार पर 10.15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें।

टमाटर की यह किस्में जिनकी खेती से होगा किसानों को फायदा

भोपाल। टमाटर एक ऐसी ही फसल है जो भारतीय लोगों द्वारा रोजाना खाई जाती है, जिससे इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। ऐसे में किसान टमाटर की वैज्ञानिक खेती कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए तापमान का बहुत बड़ा योगदान होता है। टमाटर की खेती के लिए 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान उपयुक्त रहता है। टमाटर जिस भूमि में लगाया जाता है वहां जल का जमाव नहीं होना चाहिए। अत: किसानों को जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था करना चाहिए। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए भूमि का पी-एच मान 6-7 के मध्य होना चाहिए। किसान इसकी खेती के लिए उन्नत एवं संकर किस्मों के बीज की बोवनी नर्सरी में करें। सितंबर माह टमाटर की बोवनी के लिए उपयुक्त रहता है।

अगेती किस्में

1. गोल्डन
2. पूसा हाइब्रिड-2
3. पूसा सदाबहार
4. पूसा रोहणी
5. पूसा-120
6. पूसा गौरव
7. काशी अभिमान
8. काशी अमृत
9. काशी विशेष
10. पीएच-4
11. पीएच-8

बीज की मात्रा और दूरी

टमाटर का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर प्रजातियों के लिए 250-300 ग्राम और और उन्नत प्रजातियों के लिए 500-600 ग्राम प्रति हेक्टयर बीज की मात्रा का उपयोग किसान कर सकते हैं। टमाटर की बोवनी किस्मों की रोपाई 60-60 से.मी. तथा अधिक बढ़ने वाली किस्मों की रोपाई। 5-90-60 से.मी. पर करें।

खाद का प्रयोग

टमाटर की रोपाई के समय प्रति हेक्टेयर 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद या 80 क्विंटल नाडेप कम्पोस्ट के साथ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 60-80 किलोग्राम पोटाश, 20-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 8-12 किलोग्राम बोरेक्स का छिड़काव करें। संकर/असीमित बढ़वार किस्मों के लिए प्रति हैक्टर 50-55 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करें।

-वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 25वीं बैठक में लिए कई निर्णय, कृषि वैज्ञानिकों ने दिए सुझाव और बोले

बाजार के अनुरूप तैयार हों किसान, ताकि बन सकें स्वाबलंबी

संवाददाता, भिंड

भिंड जिले के लहार कृषि विज्ञान केंद्र में गत दिवस वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 25वीं बैठक डॉ. एसआरके सिंह, निदेशक, अटारी, जबलपुर के मुख्य आतिथ्य में और डॉ. नीरज हाड़ा (वैज्ञानिक) निदेशालय विस्तार सेवाएं, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें भिंड जिले के अन्य अधिकारी व कर्मचारियों के साथ 64 लोग उपस्थित रहे। बैठक में डॉ. रूपेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा खरीफ 2021 में आयोजित गतिविधियों के अंतर्गत प्रक्षेत्र परीक्षण, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रसार गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुतीरण के माध्यम से प्रस्तुत की गई। डॉ. एसआरके सिंह, निदेशक, आंचलिक कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान (अटारी), जबलपुर ने

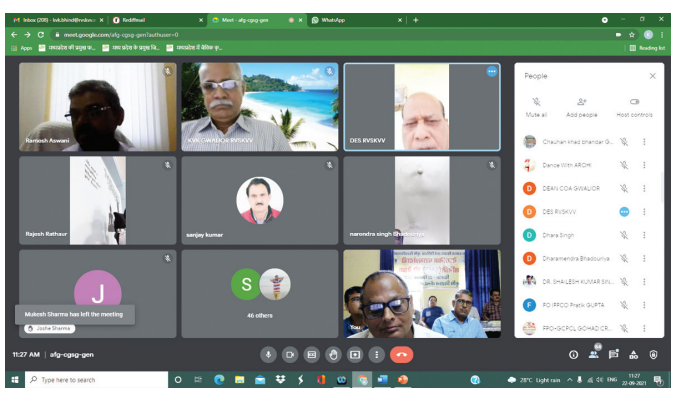

कृषि विज्ञान केंद्र, लहार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे सतत प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि किसानों को बाजार के अनुरूप तैयार करना तथा अपने उत्पाद को कहां और कैसे बेंचे इसके ऊपर जोर देने को कहा। जिससे हमारा किसान स्वाबलंबी बन सकें। जिले में ज्यादा से ज्यादा सफलता की कहानियां बन सकें। इसके बाद रबी 2021-22 में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस बैठक में डॉ. एसएन उपाध्याय, निदेशक विस्तार सेवाएं, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए केन्द्र द्वारा संचालित गतिविधियों की प्रशंसा की और आगामी कार्य योजना के लिए आवश्यक सुझाव दिए। डॉ. राज सिंह कुशवाह, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृ.वि.के, ग्वालियर ने लहार केंद्र के क्रियाकलापों की सराहना करते हुए बताया कि केंद्र विषम परिस्थितियों में भी किसानों के हित में बेहतर कार्य कर रहा है। अन्य उपस्थित वैज्ञानिकों ने भी कृषि विज्ञान केंद्र लहार के कार्यकलापों की सराहना की। इसी दौरान उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों और किसानों ने उद्यानिकी फसलों के प्रदर्शनों के आयोजन के लिए सुझाव दिया और कहा कि जिले में उद्यानिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पशुपालन विभाग से उपस्थित डॉ. मनोज शर्मा, पशु-चिकित्सिक, लहार ने केंद्र पर उपस्थित मुर्गीपालन व बकरी पालन इकाइयों का भ्रमण किया। साथ ही सराहना करते हुए कहा कि केन्द्र द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों के चलते जिले में मुर्गी पालन और बकरी पालन के क्षेत्र में बढ़ावा होगा।

-मऊंगज के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्र का नवाचार

विंध्य का शंख दरियाब नींबू पथरी के इलाज के लिए रामबाण

संवाददाता, भोपाल/रीवा

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था- कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी का एक उदाहरण रीवा जिले की तहसील मऊगंज के ग्राम पंचायत मऊबगदरा में देखने को मिल रहा है। विंध्य में खेती-किसानी में नवाचार के लिए चर्चित प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्र एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल, किसान अनिल कुमार मिश्र ने अपने घर पर प्रयोग के तौर पर शंख दरियाब नींबू के पौधे लगाए। जिसमें उम्मीद से बढ़ कर अब फल आ रहे हैं। यह नींबू सुर्खियों के साथ आकषर्ण का केंद्र इसलिए बना हुआ है, क्योंकि पथरी (स्टोन) से पीड़ित लोंगों के लिए शंख दरियाब नींबू रामबाण माना गया है। कहा जाता है कि पथरी पीड़ित व्यक्ति अगर शंख दरियाब नींबू का सेवन एक सप्ताह कर ले तो उसे आराम मिल जाएगा। यानी उसकी पथरी अपने आप गल कर गिर जाएगी। मध्यप्रदेश, बिहार, तमिलनाडू, कर्नाटक, आंध्रा, गुजरात और भी कई सारे राज्यों के किसान बड़ी मात्रा में नींबू की खेती कर रहे हैं। वहीं मप्र के किसान अब देशी नींबू की खेती के साथ शंख दिरयाब नींबू की खेती भी शुरू कर दिए हैं। जो औषधीय के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। इससे तय है कि किसानों की आय में इजाफा होगा और वो आत्मनिभर मप्र के सपने को भी साकार करेंगे।

तीन किलो का एक नींबू

शंख दरियाब नींबू की खासियत यह है कि इसका आकार पपीते जैसा होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नींबू का बजन तीन किलो से ज्यादा का होता है। अनिल कुमार बताते हैं कि पहली बार जब फल लगे थे, तब 60-70 थे, लेकिन दूसरी बार जब फल लगे तो डेढ़ सौ से ऊपर थे। जैसे-जैसे नींबू का पेड़ विकसित हो रहा, वैसे ही फलों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इस साल करीब पांच सौ नींबू लगे थे।

जरूरतमंदों को दे रहे

जानकारी लगने पर किसान अनिल कुमार मिश्र के यहां जिल के अलावा, भोपाल, दिल्ली, बनारस, मिर्जापुर, महाराष्ट्र, हैदराबाद सहित आद राज्यों से जरूरतमंद लोग पहुंच रहे हैं। जिन्हें अभी नींबू दिया जा रहा है। जरूरतमंदों से अनिल कोई पैसा नहीं लेते हैं। उनका कहना है कि जब शंख दरियाब नींबू की बगिया तैयार हो जाएगी और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगेगा तब वो इसे बाजार में बेचेंगे।

दिल्ली से लाए थे पौधा

गत वर्ष दिल्ली किसान केंद्र में देशभर के प्रगतिशील किसानों को सम्मान के लिए जब आमंत्रित किया गया था। तब अनिल कुमार भी गए थे। उन्हें भी तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह सम्मानित किया था। सम्मान समारोह के बाद वहीं कहीं से वो शंख दरियाब का एक पौधा लाए थे। जो अब फल देने लगा है।

- » तीन से चार किलो का नींबू बना लोगों के आकषर्ण का केंद्र
- » दिल्ली से लाए थे एक पौधा, अब बगिया लगाने की तैयारी
- » नींबू के रस का सेवन करने पर कफ की समस्या हो रही दूर
- » साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो हड्डियों को करता है मजबूत
- » इम्यून सिस्टम को मजबूत करने नींबू का सेवन करना चाहिए
- » डायरिया होने पर भी नींबू के रस का सेवन अत्यधिक फायदेमंद
- » नींबू की खेती से किसानों को हो रहा लाखों का मुनाफा

जागरुक किसान

विश्व में देखा जाए तो भारत नींबू उत्पादन में 5वा स्थान रखता है। नींबू के पौधों को पूरे भारत में कहीं भी उगाया जा सकता है। यदि व्यवसायिक तौर पर इसकी खेती करने वाले राज्यों को देखे तो पंजाब, राजस्थान,उत्तरप्रदेश के तराई क्षेत्र लेकिन अब इसकी खेती के प्रति जागरूकता बढ़ने के बाद, कई राज्यों में इसकी खेती सफलता पूर्वक किसान कर रहे हैं।

जलवायु और मिट्टी

नींबू का फल कोमल होता है और जैसा कि इसकी खेती पूरे देश में हो सकती है, लेकिन यदि व्यवसायिक तौर पर इसकी खेती करनी है तो उन क्षेत्रों में इसे ना लगाया जाए जहां पाला ज्यादा गिरता हो। तेज हवाएं चलती हों। जहां 750 मिमि से वर्षा ज्यादा ना होती हो। देखा जाए तो जहां जलवायु सूखा हो, बारिश कम हो वहां नींबू की खेती अच्छी रहती है और नींबू अच्छी ग्रोथ भी करता है। नींबू की खेती सभी तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन हल्की दोमट जल निकास वाली मिट्टी इसके लिए अनुकूल मानी गई है।

चुनिंदा प्रजाति के नींबू

मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में पाए जाने वाले चुनिंदा नींबू में कागजी, प्रमालिनी, विक्रम नींबू, चक्रधर, पीकेएम, साई शरबती, देशी और सीडलेस नींबू को किसान बड़ी मात्रा में उगा रहे हैं।

औषधीय गुण

एक तरफ विटामिन सी भरपूर मात्रा में होने की वजह से नींबू के कई औषधीय गुण होते हैं तो वहीं इसका स्वाद चाहे अचार के रूप में हो या नींबू पानी और शिकंजी के रूप में बहुत खास है। इसे सलाद और खाद्य पदार्थों में डालकर भी खाया जाता है।

1. 85 लाख किसानों से 4.39 लाख टन खरीदी, समर्थन पर धान, बाजरा-ज्वार की होगी खरीदी

प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की भी रिकॉर्ड खरीदी

विशेष संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश ने गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीद के बाद समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इस बार एक लाख 85 हजार किसानों से चार लाख 39 हजार 437 टन मूंग खरीदी गई है। जबकि, केंद्र ने प्रदेश को दो लाख 47 हजार टन मूंग खरीदने की विशेष अनुमति दी थी। अब सरकार ने धान, बाजरा और ज्वार समर्थन मूल्य पर खरीदने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसके लिए पंजीयन 14 अक्टूबर तक होगा। प्रदेश में इस बार आठ लाख 36 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की गई थी। राजस्व विभाग के सर्वे के अनुसार 12 लाख 16 हजार टन मूंग का उत्पादन हुआ। केंद्र ने प्रदेश को प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत पहले 34 हजार टन मूंग खरीदने की अनुमति दी थी, जिसे बाद में एक लाख टन और बढ़ाया गया। किसानों की मांग और उत्पादन को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से खरीद लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया। तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह को भी कृषि मंत्रालय में चर्चा के लिए भेजा गया।

केंद्र ने दे दी अनुमति

सरकार की पहल का असर यह हुआ कि केंद्र ने कुल दो लाख 47 हजार टन मूंग समर्थन मूल्य एक हजार 796 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की अनुमति दे दी। यह लक्ष्य भी जल्द ही पूरा हो गया, क्योंकि तीन लाख 27 हजार 72 किसानों ने पंजीयन कराया था। अधिकारियों ने बताया कि इसके पहले कभी इतनी ग्रीष्मकालीन मूंग नहीं खरीदी गई। प्रदेश ने 2020 में एक करोड़ 29 लाख टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदकर देशभर में रिकॉर्ड बनाया था।

मध्यप्रदेश में मूंग की बंपर पैदावार हुई है। हमने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आग्रह किया कि हमने जो मूंग खरीदी है। उसके लिए भी भारत सरकार से अनुमति मिले। तोमर ने हर विषय पर भारत सरकार द्वारा सहयोग देने का आश्वासन दिया है जिसके लिए उन्हें सादर धन्यवाद देता हूं। कृषि अधोसंरचना का विकास तेजी से हो रहा है, जिससे प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। हमने खाद की उपलब्धता के बारे में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि उर्वरक की आपूर्ति आवश्यकतानुसार प्रदेश को की जाएगी। मूंग की खरीदी हेतु भी हम उनके आभारी हैं।

-शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

रिकॉर्डतोड़ हुई थी धान खरीदी

पिछले साल 37 लाख टन से ज्यादा धान खरीदकर मध्य प्रदेश ने अपना 2019 का रिकॉर्ड तोड़ा था। तब 25 लाख 86 हजार टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि अब धान, बाजरा और ज्वार समर्थन मूल्य पर खरीदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य एक हजार 940, ज्वार का दो हजार 738 और बाजरा का दो हजार 250 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)